

हरियाणा के सरकारी स्कूलों पर रपिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

एक हालिया सरकारी रपिपोर्ट से पता चला है कि राज्य में 19 स्कूल बना किसी छात्र के हैं, 811 स्कूलों में सरिफ एक शकिषक है और कुल 3,148 स्कूलों में उनकी कषमता के आधे से भी कम छात्र हैं।

मुख्य बदि:

- रपिपोर्ट, जिसमें फरवरी 2024 में केंद्रीय शकिषा मंत्रालय के परयोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा आयोजित एक बैठक के मुख्य बदिओं को रेखांकित किया गया, जिसमें राज्य के 14,562 सरकारी स्कूलों को चहिनति किया गया।
- रपिपोर्ट ने वशिषकर प्राथमिक वदियालयों में शकिषकों की अपर्याप्त संख्या पर प्रकाश डाला और सरकार को इन रकिर्तियों को तुरंत भरने की सलाह दी।
- शकिषकों की कमी का असर वेतन भुगतान के लिये आवंटित केंद्रीय धनराशिपर पड़ा है।
- प्राथमिक क्षेत्र में, वत्तीय सहायता वर्ष 2021-22 की अवधि में 19 लाख रुपए से घटकर 14 लाख रुपए हो गई है।
- इसी तरह, उच्च शकिषा में कई रकिर्त पदों के कारण अनुदान 20 लाख रुपए से घटकर 14 लाख रुपए हो गया है।
- रपिपोर्ट में शकिषकों की कमी के अलावा इन स्कूलों में छात्रों के लिये बुनियादी ढाँचे की कमी की भी बात कही गई है।
- जबकि स्कूल अतरिकित कक्षाओं के अपने लक्ष्य से 18% कम हैं, लड़कों और लड़कियों के लिये शौचालय 1% व 1.8% कम हैं। स्मार्ट क्लासरूम भी आवश्यक संख्या से 1.4% कम हैं।
- रपिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि अतीत की गैर-आवर्ती स्वीकृतियाँ, जनि पर वर्षों से राज्य द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है, अंततः **समग्र शकिषा फरेमवरक** के अनुसार 5 वर्ष की अवधि के बाद राज्य की एकमात्र ज़मिमेदारी बन जाएंगी।
- जनि स्कूलों ने सुवधिएँ स्थापति नहीं की हैं, उन्हें अपने प्रारंभिक प्रस्ताव वापस लेने चाहिये और नए प्रस्ताव के बारे में सोचना चाहिये।
- प्रस्तुत आँकड़ों में किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने के लिये राज्य सरकार को लंबित कार्यों की प्रगतिको नथिमति रूप से **प्रबंध पोर्टल** पर अपडेट करने का नरिदेश दिया गया है।

समग्र शकिषा योजना

- यह स्कूली शकिषा के लिये एक एकीकृत योजना है, जिसमें प्री-स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा तक की शकिषा संबंधी सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।
- इसका उद्देश्य समावेशी, न्यायसंगत और सुगम स्कूली शकिषा प्रदान करना है।
- यह 'सर्व शकिषा अभियान' (SSA), 'राष्ट्रीय माध्यमिक शकिषा अभियान' (RMSA) और 'शकिषक शकिषा' (TE) की तीन योजनाओं को समाहित करती है।
- इस योजना में 1.16 मिलियन स्कूल, 156 मिलियन से अधिक छात्र और सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों के 5.7 मिलियन शकिषक (पूर्व-प्राथमिक से वरषिठ माध्यमिक स्तर तक) शामिल हैं।
- इसे केंद्र परायोजित योजना के रूप में लागू किया जा रहा है। इसमें केंद्र और अधिकांश राज्यों के बीच वत्तिपोषण में 60:40 का वभिजन शामिल है। इसे वर्ष 2018 में शकिषा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।

समग्र शकिषा योजना 2.0

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer- DBT):**
 - योजना की प्रत्यक्ष पहुँच को बढ़ाने के लिये सभी बाल-केंद्रित हस्तक्षेप छात्रों को सीधे सूचना प्रौद्योगिकी-आधारित प्लेटफॉर्म पर DBT मोड के माध्यम से समय-समय पर शकिषा का अधिकार पात्रता के तहत पाठ्यपुस्तक, ड्रेस और परविहन भत्ते प्रदान किये जाएंगे।
- NEP की सफिरशें:**
 - भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन:
 - इसमें भाषा शकिषकों की नयिकृति के लिये एक नया घटक है, जिसमें वेतन और प्रशकिषण लागत के साथ-साथ द्वभिषी कतिाबें तथा शकिषण सामग्री शामिल है, जैसा कि NEP में अनुशंसित किया गया है।

- **पूरव पूरथमकि शकिषा:**
 - इसमें अब शकिषण एवं अधगिम सामगरी, स्वदेशी खलौने और खेल तथा खेल-आधारति गतविधियों के लयि सरकारी स्कूलों में पूरव-पूरथमकि वर्गों को समर्थन देने के लयि वतित प्रदान करना शामिल होगा ।
 - योजना के तहत पूरव-पूरथमकि शकिषकों और आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं के लयि कुशल प्रशकिषकों का समर्थन कयिा ज़ाएगा ।
- **नपिण भारत पहल:**
 - इस पहल के तहत शकिषण सामगरी के लयि प्रतति छात्र 500 रुपए, मैनुअल और संसाधनों के लयि प्रतति शकिषक 150 रुपए तथा आधारभूत साकषरता एवं अंकगणति के आकलन के लयि प्रतति ज़िले 10-20 लाख रुपए का वार्षकि प्ऱावधान है ।
- **डजिटिल पहल:**
 - डजिटिल बोरड, वर्चुअल क्लासरूम और DTH चैनलों के लयि समर्थन सहति ICT लैब तथा स्मार्ट क्लासरूम का प्ऱावधान है, जो कोवडि-19 महामारी के मद्देनज़र अधकि महत्त्वपूरण हो गए हैं ।
- **स्कूल न जाने वाले बच्चों हेतु:**
 - इसमें 16 से 19 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चों को ओपन स्कूलगि के माध्यम से अपनी शकिषा पूरी करने के लयि 2000 प्रतति ग्रेड के वतितपोषण का समर्थन देने का प्ऱावधान शामिल है ।
 - स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों दोनों के लयि कौशल तथा व़्यावसायकि शकिषा पर भी अधकि ध्यान दयिा ज़ाएगा ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/report-on-haryana-government-schools>

